

वन विभाग के पलाश सभागार में विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस का आयोजन

मरुस्थलीकरण रोकने के लिये तैयार होगा विजन डॉक्यूमेंट : रस्तोगी

नवप्रदेश संवाददाता
रांची : झारखंड राज्य में करीब 20 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र ऐसा है, जिसमें कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है, वहां सिर्फ प्लांटेशन का काम किया जा सकता है। वहीं इन क्षेत्रों में तकनीकी कमी की वजह से वर्षा जल के संचयन का कार्य नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से झारखंड की मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। उक्त बातें झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख एके रस्तोगी ने डोरंडा स्थित पलाश सभागार में आयोजित विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूख रोकथाम दिवस पर आयोजित प्चूर रेडी



झारखंड कार्यक्रम में कही।

एके रस्तोगी ने कहा कि झारखंड की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने के लिये दीर्घकालीन योजना तैयार करने की जरूरत है, जो जल और जंगल है

उन्हें बचाने के लिये वन विभाग के सभी स्तर के कर्मचारियों और पदाधिकारियों को कार्ययोजना तैयार कर उसे कार्यान्वित करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि इस दिशा में काम नहीं हुआ है, काम

तो हुए हैं लेकिन हम विभाग के कार्यों का दस्तावेजीकरण नहीं कर सकते हैं जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है। इसलिए जो भी बीते दशकों में किये गये कार्यों का मॉनिटरिंग इंडेक्स है, उसे लेकर भविष्य की योजना तैयार करने की जरूरत है।

संगोष्ठी में विभिन्न जिलों से आये जिला वन पदाधिकारियों ने अपने सुझाव देते हुए कहा कि नर्सरी को लेकर और ज्यादा अच्छा काम करने की जरूरत है। साथ ही बंद पड़ी खदानों को टेकओवर कर उन क्षेत्रों में भी पौधरोपण का कार्य किया जा सकता है और वन क्षेत्रों में लाइवलीवुड को प्राथमिकता देकर स्थिति में बदलाव की संभावना है। पदाधिकारियों

ने कहा कि हमें सूखे की समस्या से निपटने के लिये अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करना होगा ताकि 2030 के 32 गीगा टन कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में कदम बढ़ा सकें।

कार्यक्रम में दो पुस्तिकाओं का भी लोकार्पण किया गया। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूख रोकथाम दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी प्रतिपालक श्री आशीष रावत, प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह कार्यकारी निदेशक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव सहित राज्य के विभिन्न जिलों से आये वन पदाधिकारी उपस्थित थे।

रांची हिंसा की पूरी जानकारी कोर्ट को उपलब्ध कराये सरकार : हाई कोर्ट



►‘पोस्टर लगाजा चाहिए या नहीं इसका फैसला कोर्ट नहीं करेगी’

नवप्रदेश संवाददाता

रांची : झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रविंरंजन और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की बेंच में शुक्रवार को गत दस जून को रांची के मेन रोड में हुए हिंसा मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि इंटीलिजेंस को मामले की जानकारी थी या नहीं, सरकार इसकी जानकारी दे।

हिंसा के आरोपित गिरफ्तार नवाब चिश्ती पर सरकार की ओर से कहा गया कि मंत्री के साथ भले ही नवाब की तस्वीर हो लेकिन मंत्री की नवाब के साथ कोई जान-पहचान नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि घटना के तार बड़े लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। कोई किसी के साथ कैसे फोटो खिंचवा सकता है।

पोस्टर मामले पर कोर्ट ने कहा कि पोस्टर लगना चाहिए या नहीं इसपर फैसला नहीं होगा। इस मामले पर सरकार जवाब दे। कोर्ट

ने कहा कि एक साथ कैसे दस हजार लोग जमा हो गए। कोर्ट ने सरकार घायल, मृतकों और कितनी राउंड गोiliar चलीं इसकी भी जानकारी मांगी है।

उल्लेखनीय है कि इससे एक दिन पहले हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ टिप्पणी करते हुए जवाब मांगा था। हाई कोर्ट ने विधि व्यवस्था की खराब स्थिति के मद्देनजर सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने को कहा था। हाई कोर्ट में इस मामले से जुड़ी याचिका आरटीआई एक्टिविस्ट पंकज कुमार यादव ने दाखिल की है।

दायर याचिका में पंकज कुमार यादव ने हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, रांची के उपायुक्त, एसएसपी, मुख्य सचिव, एनआइए, ईडी और आयकर आयुक्त को पार्टी बनाया है। अदालत से इस मामले की एनआईए से जांच की मांग की गयी है। इस याचिका में सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम देने की बात की गयी है, जिसमें संगठनों के फंडिंग की बात भी कही गयी है।

बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा है अग्निपथ योजना : कांग्रेस

नवप्रदेश संवाददाता

रांची : कांग्रेस ने कहा है कि केन्द्र सरकार की ओर से भारतीय सेना की रेग्युलर भर्ती रोक कर चार साल के ठेके पर फौज की भर्ती करना देश के युवाओं के साथ धोखा है। यह भारतीय सेना की गरिमा, परम्परा, जुड़ाव की भावना एवं अनुशासन की परिपाटी के साथ खिलवाड़ भी है।

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश किरण महतो ने शुक्रवार को कहा कि केन्द्र सरकार ने देश में ढाई लाख से भी अधिक पद खाली रहने के बावजूद पिछले दो साल से सेनाओं की भर्ती रोक

रखी है। हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा कर केन्द्र में आई। इस सरकार के समक्ष जब सेना में नौकरी देने की बारी आई तो वह ऐसी योजना लेकर आ गई जिसमें बहाल हुए सैनिकों का भविष्य ही अंधकार में होगा।

उन्होंने कहा कि दरअसल निजीकरण और पूंजीवाद की राह में अग्रसर यह सरकार देश में गुंजायमान एवं लाचार बेरोगारों की फौज खड़ा करना चाहती है। महतो ने बताया कि रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि चार साल की कॉन्ट्रैक्ट भर्ती की यह योजना देश की सुरक्षा के लिए उचित संदेश नहीं है। यह निर्णय कहीं न कहीं तीनों सेनाओं

की कार्यक्षमता, निपुणता, योग्यता, प्रभावशीलता और सामर्थ्य पर समझौता करने वाला है। इससे सेना की कार्यशील क्षमता घटेगी।

महतो ने कहा कि इस भर्ती योजना से पूरे देश के युवा आक्रोश में है और वे इसका उग्र विरोध कर रहे हैं। यह योजना विवादित है और इसमें कई तरह के खतरे भी हैं। इसलिए इसे तत्काल स्थगित कर देना चाहिए तथा केन्द्र सरकार को कार्यरत और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों से सलाह माशविरा लेना चाहिए। इस योजना को लाने में जल्दबाजी की गई है। इसी वजह से इसमें कई तरह की खामियां हैं।

सेना जैसे संवेदनशील संस्थान में सविदा भर्ती करना अविवेकपूर्ण फैसला : आभा सिन्हा

रांची : प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता आभा सिन्हा ने केन्द्र सरकार के अग्निपथ योजना के निर्णय को अविवेकपूर्ण फैसला करार देते हुए कहा है कि पूरे देश में जिस तरह युवा आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके मद्देनजर केन्द्र सरकार को इसे अविलंब वापस लेना चाहिए। आभा सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य एवं देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है। देश के लाखों युवा देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होते हैं। अग्निपथ योजना से झारखंड सहित भारत के लाखों युवाओं में रोष एवं नाराजगी है। पूरे देश में जिस तरह युवा आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसे देखते हुए इस योजना को केन्द्र सरकार अविलंब वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना जैसे संवेदनशील संस्थान में सविदा भर्ती करना अविवेकपूर्ण फैसला है। सेना को अभी तक गैर-राजनीतिक एवं वित्तीय बंधनों से मुक्त रखा गया।

तसर संस्थान में अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक तथा जैव प्रौद्योगिकी पर विचार मंथन

स्टार्टअप से काफी आगे जायेगा रेशम उद्योग

नवप्रदेश संवाददाता

रांची : केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगड़ी, रांची में अनुसंधान सलाहकार समिति की 50वीं बैठक तथा जैव प्रौद्योगिकी पर विचार मंथन सत्र का आयोजन किया गया। इस बैठक में कुल 13 संचालित परियोजनाओं एवं 02 सम्पन्न परियोजनाओं की समीक्षा की गयी। साथ ही 19 अनुसंधान संकल्पना नोट पर भी चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रो. ओंकार नाथ सिंह, कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची ने की। बैठक में डॉ.एन.कृष्ण कुमार, अध्यक्ष, आरएससी, एसबीआरएल, बेंगलुरु को विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया था। बैठक के आरम्भ में संस्थान के निदेशक डॉ.के. सत्यानारायण ने अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में संस्थान द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि संस्थान में तसर रेशम के उप उत्पादों/अवशिष्टों के द्वारा मूल्यवर्धन की दिशा में कार्य प्रगति पर हैं इससे भविष्य में अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध



होंगे। बैठक में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित डॉ.एन.कृष्ण कुमार ने विचार विकास पर फोकस कर रहे हैं। स्टार्टअप के बारे में अब आम धारण बदल रही है। हमें अपने निम्नतर आय वर्ग का सहयोग करना होगा तथा उन्हें अधिकाधिक लाभान्वित करने पर अपने अनुसंधानों को केद्रित करना होगा। हमें रेशम वस्त्र की उत्पादन लागत, प्रौद्योगिकी लागत को कम करने की दिशा में भी अनुसंधान करने की आवश्यकता है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग,

नई दिल्ली से उपस्थित डॉ. असलम, सलाहकार ने कहा कि अब हम प्रौद्योगिकी विकास पर फोकस कर रहे हैं। स्टार्टअप के माध्यम से रेशम उद्योग को काफी आगे ले जाया जा सकता है। हमें समय की माँग के अनुरूप अनुसंधान परियोजनाएं प्रतिपादित करनी होंगी।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रो.ओंकार नाथ सिंह ने सर्वप्रथम संस्थान की 50वीं (स्वर्ण जयंती) बैठक के लिए सभी को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा

कि हमें जैव प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी को अनुसंधान के क्षेत्र में अद्यतित करना होगा। इसके लिए युवा वैज्ञानिकों को नवीनतम् टूल्स का उपयोग करते हुए ऐसे अनुसंधान करने चाहिए जिससे इस उद्योग से जुड़ी गरीब एवं आदिवासी आबादी को सीधा लाभ मिल सके। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से रेशम उद्योग के क्षेत्र में आगामी कार्य करने की अपार संभावनाएँ हैं।

इस अवसर पर केन्द्रीय तसर

अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगड़ी, रांची का बिरसा कृषि विश्वविद्यालय तथा तसर विकास संघ, देवघर के साथ तसर क्षेत्र में अनुसंधान एवं विस्तार पर दो समझौता ज्ञापन की हस्ताक्षरित किए गए। इस दौरान चार तकनीकी प्रसार बुलेटिन का विमोचन भी किया गया।

इस अवसर पर डॉ. सुभाष नायक वी., निदेशक, केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु, डॉ. नितिन कुलकर्णी, निदेशक, वन उत्पादक संस्थान, रांची, डॉ. अरुणव पटनायक, निदेशक, आईआईएबी, रांची, डॉ. पीके मिश्रा, निदेशक (सेवानिवृत्त), केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु, डॉ. एन.कुदादा, रिजस्ट्रार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची, डॉ. शमशाद आलम, प्रदान, झारखण्ड, निरंजन तिवारी, उप निदेशक, रेशम निदेशालय, झारखण्ड तथा डॉ.एस.मथिरा मूर्ति, वैज्ञानिक-डी, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूर भी उपस्थित थे। बैठक में संस्थान के समस्त वैज्ञानिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन सुमिता दास, वैज्ञानिक-डी ने किया।

एक नजर

सीएम ने ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को दिया अवधि विस्तार

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी जिलों में विगत आठ वर्षों से सविदा आधारित पद पर कार्यरत ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की अवधि दो वर्ष (अक्टूबर, 2021 से सितम्बर, 2023) तक विस्तारित करने के मामले में विमर्श हेतु दिये गये निदेश के आलोक में विमर्शोपरांत दिये गये प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया है। मालूम हो कि जिला स्तर में ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके द्वारा डिजिटल कार्यों से जुड़ा कार्य किया जाता है। एक समग्र उद्देश्य के साथ ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर स्थानीय स्तर के ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित भाव से जिला के उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट को सहयोग प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा दिये अवधि विस्तार से जिला स्तर पर डिजिटल एवं ऑनलाइन सेवा से जुड़े कार्यों को रफ्तार मिलेगी।

पुल निर्माण हेतु मिली स्वीकृति

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने गोमिया एवं डुमरी बिहार स्टेशन के बीच पेटेरवार गोमिया नरकी विशुनगाढ़ पथ के चैनैज 26.150 किमी में एलसी नं.- 11/ए/टी के स्थान पर पथ उपरी पुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण कार्य हेतु रू० 83.31,96,390 /- (तैरासी करोड़ एकतीस लाख छियानबे हजार तीन सौ नब्बे रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं रेलवे द्वारा पथ उपरी पुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण हेतु आवश्यक राशि की अग्रिम निकासी कर राशि (भू-अर्जन की राशि को छोड़कर) रेलवे को उपलब्ध कराने की स्वीकृति संबंधी मंत्रिपरिषद् एवं योजना प्राधिकृत समिति हेतु संलेख प्रारूप पर अनुमोदन की स्वीकृति दी।

सीएम ने अभियंता प्रमुख के खिलाफ दिया एसीबी जांच का आदेश

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने रास बिहारी सिंह, तदेन प्रभारी अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध प्राप्त परिवाद के आलोक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज आई.आर. सं०-06/17 के सत्यापनकर्ता द्वारा आरोपी के विरुद्ध आय की तुलना में व्यय 199 प्रतिशत अधिक पाये जाने के आलोक में पीई दर्ज करने के बिन्दु पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी), झारखण्ड रांची को अनापत्ति संसूचित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया।

सुदेश महतो का जन चौपाल आज

रांची : झारखंड के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं आजसू पार्टी के केन्द्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो कल मांडर उपचुनाव को लेकर जन चौपाल करेंगे। ज्ञात हो कि 23 जून को मांडर विधानसभा के लिए निर्धारित है। सुदेश कुमार महतो मांडर की कई पंचायतों में जनता से सीधा संवाद कर एनडीए की उम्मीदवार एवं भाजपा नेत्री गंगोत्री कुजूर के पक्ष में वोट करने हेतु जनता से अपील करेंगे। जिन पंचायतों में कल का कार्यक्रम निर्धारित है, उसमें बेड़ो, टेरो, करंजी, पुरियो एवं जरिया पंचायत मुख्य रूप से शामिल है। मांडर प्रस्थान के पश्चात सुदेश कुमार महतो पहले टेरो पंचायत के ग्राम पाकल मेढी में जन चौपाल करेंगे, फिर करंजी पंचायत एवं पुरियो पंचायत के खदीला मार्च तथा जरिया में जनता से संवाद करेंगे। जन चौपाल में आजसू एवं भाजपा के कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।

मुंडा सभा की मुंडारी नृत्य प्रतियोगिता 25 जून को

रांची : मुंडा सभा रांची की ओर से 25 जून को पुराना विधानसभा परिसर स्थित सभागार में मुंडारी नृत्य प्रतियोगिता आयोजित किया जायेगा। विधायक नमन विक्सल कांगाड़ी इसके मुख्य अतिथि होंगे। जबकि मेयर आशा लकड़ा, विधानक जोगा सुसारन होरो, विधायक कच्छप और विधायक विकास कुमार मुंडा बतौर विशिष्ट अतिथि आमंत्रित हैं। मुंडा सभा के सुनील कुमार ने बताया कि इसमें सिर्फ छह नृत्य दलों को शामिल किया जायेगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वालों को क्रमशः पांच, तीन और दो हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन 20 जून तक होगा।

हत्या के मामले में तीन आरोपित दोषी करा

रांची : रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त की कोर्ट ने सुरेंद्र राय हत्या मामले में तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने और गवाहों के बयान के आधार पर संदीप थापा, चंद्र मौली सिंह और सुजीत सिन्हा को दोषी करार दिया है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों रांची में गोलीबारी के केस में संदीप थापा को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है। अदालत सजा की विंदु पर 25 जून को सुनवाई करेगा । यह मामला वर्ष 2008 का है। नामकुम थाना क्षेत्र में सुरेंद्र राय की हत्या हुई थी। इसमें संदीप थापा सहित अन्य पांच आरोपित बनाये गये थे । हत्याकांड को साबित करने के लिए पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा किये थे और गवाहों के बयान दर्ज करवाये थे।

नाबालिग से दुकर्म के दोषी को दस साल की सजा

रांची : पाँक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से दुकर्म मामले में छोटेवा लोहरा उर्फ प्रताप लोहरा को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार का जुमाना भी लगाया है। जुमाना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इससे पूर्व 14 जून को अदालत ने लोहरा को दोषी करार दिया था। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच लोगों की गवाही कराई गई थी। इसके बाद कोर्ट ने तमाम गवाहों को सुनने और सबूतों को देखने के बाद छोटेवा लोहरा को दोषी पाया था। अधिवक्ता के अनुसार यह मामला सोनहातू थाना क्षेत्र का है। दस मई, 2019 को शौच के लिए घर से निकली नाबालिग के साथ दुकर्म हुआ था।

कोरोना के 76 सक्रिय मामले में सबसे अधिक 38 रांची में

रांची : झारखंड में कोरोना के 76 सक्रिय मामले में सबसे अधिक रांची में 38 केस सक्रिय है। शुक्रवार को बताया गया कि इन 34 घंटों में कोरोना से छह मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य के पांच जिले से कोरोना के 16 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार देवघर से तीन, पूर्वी सिंहभूम (जगन्नेशदुर्ग)से दो, लातेहार से एक , पलामू से दो और रांची से आठ मरीज मिले है। राज्य में पांच हजार, 319 मरीजों की मौत कोरोंना से हुई है। कोरोंना का रिकवरी रेट 98.77 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.22 प्रतिशत है।

22 जून कोराज्य में संकल्प दिवस मनायेगी आजसू पार्टी

रांची : आजसू पार्टी 22 जून को पूरे राज्य के संकल्प दिवस मनाएगी। इसे लेकर सभी पदाधिकारियों को दिशानिर्देश दिया गया है। संकल्प दिवस के अवसर पर आजसू पार्टी के नेता, कार्यकर्ता एवं समर्थक सभी जिला एवं प्रखंड कार्यालय में झारखंड आंदोलन में जान गंवाने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे तथा राज्य की वर्तमान स्थिति, संगठन विस्तार एवं भावी कार्यक्रमों को लेकर चिंतन-मंथन करेंगे। साथ ही राज्य की मर्यादा एवं जनमन की सुरक्षा के संकल्प के साथ-साथ वैचारिक मूल्यों को बचाने का संकल्प लेंगे। अपने-अपने क्षेत्रों में संकल्प दिवस को सफल बनाने हेतु सभी केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, जिला एवं प्रखंड के सभी पदाधिकारियों को दिशानिर्देश दिया गया है। साथ ही साथ संकल्प सभा में सभी अनुपंगी इकाई (अखिल झारखंड महिला संघ, अखिल झारखंड छात्र संघ, आजसू बुद्धिजीवी मंच, अखिल झारखंड श्रमिक संघ, अखिल झारखंड किसान संघ, अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ, अखिल झारखंड उद्योग एवं व्यापार संघ, अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा, अखिल झारखंड अल्पसंख्यक महासभा, अखिल झारखंड अनुसूचित जनजाति महासभा, अखिल झारखंड अनुसूचित जाति महासभा एवं आजसू पार्टी कला-संस्कृति प्रकोष्ठ) के पदाधिकारी शामिल होंगे।

रिम्स अराजपत्रित कर्मचारी संघ 18 जून से करेगा आंदोलन

रांची : अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रिम्स अराजपत्रित कर्मचारी संघ की ओर से 18 जून से आंदोलन किया जाएगा। इसे लेकर शुक्रवार को संघ के लोगों ने बैठक की और मांगों को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया। संघ के सदस्य महेंद्र कुमार ने बताया कि संघ 18 जून से अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करेगा। यह आंदोलन 18 से शुरू होकर 27 जून तक चलेगा। 18 और 19 जून को कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। 21 जून को संघ निदेशक कार्यालय के सामने मौन प्रदर्शन किया जायेगा। 23 जून को कलारबंद हड़ताल, 25 जून को प्रशासनिक भवन की तालाबंदी और 27 जून को सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक ओपीडी सेवा को बंद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह आंदोलन संघ डबल ईपीएफ वसूली के खिलाफ कर रहा है।

बीएयू : प्रयोगशाला पशुओं के नैतिक उपयोग पर कार्यशाला व व्यावहारिक प्रशिक्षण का समापन

अनुसंधान में पशुओं का उपयोग न्यूनतम हो : डॉ पाल

नवप्रदेश संवाददाता

रांची : बीएयू अधीन संचालित वेटनरी संकाय के पशुचिकित्सा रोग विभाग एवं निदेशात्मक पशु आचार समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जैव चिकित्सा अनुसंधान में प्रयोगशाला पशुओं के नैतिक उपयोग विषयक तीन दिवसीय कार्यशाला व व्यावहारिक प्रशिक्षण का समापन शुक्रवार को हुआ। कार्यक्रम में रांची वेटनरी कॉलेज, रिम्स, रांची एवं बीआईटी, मेसरा तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिण बिहार के कुल 55 पीजी एवं पीएचडी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने भाग लिया। समापन के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि निदेशक अनुसंधान डॉ एसके पाल ने प्रतिभागियों से कार्यशाला में मिले ज्ञान एवं



अनुभवों के बारे में जाना और उन्हें प्रमाण-पत्र प्रदान किया। संबोधन में डॉ पाल ने कहा कि मानव स्वास्थ्य चिकित्सा के खोजों में प्रयोगशाला पशुओं सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग है। जैव चिकित्सा अनुसंधान की इस प्रक्रिया में शोधार्थियों को राष्ट्रीय

एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों एवं दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए। मूक पशुओं को प्रभावित करने वाले तनाव कारक पर विशेष ध्यान देते हुए चिकित्सा अनुसंधान में पशुओं का न्यूनतम नैतिक उपयोग करना चाहिए।

कार्यशाला के विशेषज्ञ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिण बिहार के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ शक्ति प्रसाद पटनायक ने बदलते आधुनिक परिवेश में जैव चिकित्सा अनुसंधान में प्रयोगशाला पशुओं के नैतिक उपयोग में मानक तकनीकों से अवगत कराया।

स्वागत भाषण में डीन वेटनरी डॉ सुशील प्रसाद ने प्रयोगशाला पशुओं के नियमित निरीक्षण की विधियों और आनुवंशिक लक्षण, पहचान संख्या, रक्त और शरीर की कोशिकाओं का संग्रह, पूर्व और बाद के मामलेका संग्रहण, इंजेक्शन की तकनीक, पशुओं की पहचान और लक्षण, विभिन्न मार्गों

द्वारा इंजेक्शन, विभिन्न एजेंट्स का उपयोग आदि में विशेष सतर्कता बरतने की बात कही।

मौके पर प्रतिभागियों में डॉ विशाखा सिंह कार्यशाला को पशु चिकित्सा अनुसंधान में बेहद उपयोगी बताया और संकाय में नियमित तौर पर ऐसे आयोजन की जरूरत पर बल दिया। प्रतिभागियों में प्रीति मंडल एवं शशि रंजन ने भी अपने अनुभवों को साझा किया संचालन डॉ स्वाति सहाय तथा धन्यवाद पाट्यक्रम निदेशक डॉ एमके गुप्ता ने दी। मौके पर डॉ एके पांडे, डॉ सुरेश मेहता, डॉ राजू प्रसाद, डॉ प्रवीण कुमार, डॉ ग्लोरिया तिग्माएवं कॉलेज तथा रिम्स रांची के चिकित्सक डॉ नीरज कुमार, डॉ विनीता प्रसाद, डॉ पविता कुमारी, डॉ रंिकी गुप्ता एवं डॉ संजय मंडल आदि भी मौजूद थे।

सुविधाओं के अभाव में भी बिना किसी भय के हम सफल हो सकते हैं : प्रवीण वशिष्ठ

नवप्रदेश संवाददाता

खूंटी : केन्द्रीय गृह विभाग के अपर सचिव प्रवीण वशिष्ठ ने शुक्रवार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कलामाटी की छात्राओं से मिलकर उन्हें बेहतर शिक्षा की दिशा में अग्रसर होने की बात कही। छात्राओं का हासला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि सुविधाओं के अभाव में भी बिना किसी भय के हम सफल हो सकते हैं। छात्राओं ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने प्रश्नों व जिज्ञासाओं को प्रस्तुत किया।

मौके पर छात्राओं ने अपनी शिक्षा के दौरान आनेवाली बाधाओं को बताया। साथ ही समस्याओं के सामाधान भी जाने। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत खूंटी की छात्राओं को उच्चल भविष्य की ओर अग्रसर करने के उद्देश्य से उपयुक्त शशि रंजन द्वारा एक अनेखी पहल की गई है। इस पहल में सपनों की उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से जिले के छात्रों के लिए सुदृढ शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास है। इसके लिए खूंटी जिला के कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय के 11वीं एवं 12वीं की छात्राओं को भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और

गणित विषयों का विशेष शिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में सफल हो सकें।

समेकित आजीविका कृषि प्रणाली का अवलोकन किया

भ्रमण के क्रम में अपर सचिव ने अंतर्गत समेकित आजीविका कृषि प्रणाली का अवलोकन किया। मौके पर प्रवीण ने कहा कि हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए कि हम बहुमुखी प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। उन्होंने कहा कि ज़ाखण्ड में कृषि के क्षेत्र में बहुत सम्भावनाएँ हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए कि किसानों को इसका सीधा लाभ मिले। बताया गया कि फार्म को बेहतर संसाधन केंद्र बनाने के उद्देश्य से विभिन्न बिभागों के साथ समन्वय स्थापित कर अभिसरण के माध्यम से भी कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है। इन्हीं चरणबद्ध एवं नियोजित कार्यों का क्रियान्वयन करते हुए करां फार्म उदाहरण बन रहा है। मनरेगा की विभिन्न योजनाओं से शेड का निर्माण कर गाय पालन, बकरी पालन, मुगीपालन जैसे वैकल्पिक

संसाधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

वहीं दूसरी ओर मधुमक्खी पालन सह शहद उत्पादन, मछली सह बतख पालन, केचुआ खाद उत्पादन जैसी गतिविधियां भी की जा रही है। पार्क में कृषि प्रणाली को समेकित करने के लिए जेएसएलपीएस के माध्यम से पौली नर्सरी हाउस और सोलर आधारित लिफ्ट सिंचाई इकाई की स्थापना भी की गयी है। पौली नर्सरी हाउस में मिट्टी रहित पौधों को विकसित किया जा रहा है, वहीं लिफ्ट सिंचाई फार्म के कोने-कोने तक सिंचाई हो रही है। खूंटी के टाड़ु इलाकों में नए प्रकार की खेती को बढ़ावा देने के लिए ड्रैन फ्रूट की खेती एक एकड़ भूमि पर की गयी है। समेकित आजीविका कृषि फार्म न केवल एक मॉडल साइट के रूप में उभर रहा है, बल्कि आनेवाले समय में किसान पाठशाला के माध्यम से भी ग्रामीणों को प्रशिक्षित कर प्रायोगिक तरीकों से अवगत कराया जायेगा। यह फार्म किसानों के लिए एक क्षेत्र भ्रमण सह एक्सपोजर केंद्र के नाम से जाना जायेगा। दौरै के क्रम में अपर सचिव ने रनिया का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

टूगेटर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड के थीम के साथ नए अंदाज में मनेगा ओलंपिक दिवस समारोह

पदक विजेता खिलाड़ी व उनके कोच होंगे सम्मानित

नवप्रदेश संवाददाता

रांची : आगामी 23 जून से प्रारंभ हो रहे ओलंपिक दिवस समारोह को बिल्कुल नए कलेवर में मनाया जाएगा। इस अवसर पर पदक विजेता खिलाड़ी एवम उनके कोच जिला ओलंपिक एसोसिएशन एवम झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा सम्मानित किये जायेंगे। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने पद के माध्यम से सभी जिला ओलंपिक एसोसिएशन को इसके लिए निर्देशित किया है।

इस वर्ष आयोजित किये जा रहे ओलंपिक दिवस समारोह के तहत झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा रंडिवो धूम के माध्यम से वि्वज प्रतियोगिता का आयोजन ऑनएयर किया जाएगा जिसमें स्पोर्ट्स के ऊपर आधारित प्रश्न पूछे जाएँगे और विजयी 20 प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएँगे।इस अवसर पर राज्य स्तरीय

ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित होगी जिसका थीम स्पोर्ट्स फॉर सुनिटी होगा जिसमें दस बेहतरीन ड्राइंग को पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ स्पोर्ट्स एंड पीस - खेल एवं शांति के ऊपर हिंदी एवम इंग्लिश में निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित होगी जिसमें प्रत्येक वर्ग में प्रथम चार को पुरस्कार दिया जाएगा।

इस वर्ष के ओलम्पिक दिवस के अवसर पर दिनांक 23 जून को झारखंड ओलंपिक के मोरावादी स्थित परिसर में सत्र 2021 -22 से लेकर वर्तमान में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और उनके कोच को सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत उन्हें प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो प्रदान किया जाएगा। इस हेतु मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघों को अपने खिलाड़ियों एवम कोच की सूची झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन को 20 जून 2022 तक देनी होगी।

इसकी जानकारी देते हुए

जिला स्तर पर होंगे निम्न कार्यक्रम
1.रन फॉर पीस
2.साईकल फॉर एनवायरमेंट एंड फिटनेस
3.राज्य स्तरीय पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान।

झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉ मधुकान्त पाठक ने बताया कि दिनांक 23 तारिक को प्रातः 6.30 बजे मोरावादी मैदान गांधी प्रतिमा के पास से रन फॉर पीस और साइकल फॉर एनवायरमेंट का आयोजन किया जाएगा और प्रातः 10 बजे से झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के कार्यालय परिसर में सम्मान समारोह आयोजित होगा। इसके अन्य कार्यक्रमों ड्राइंग , निबन्ध और वि्वज प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों का पुरस्कार वितरण भी इसी दौरान किया जाएगा।

झारखंड के हर जिले में खुलेगा मेडिकल कॉलेज : अर्जुन मुंडा

खूंटी : जनजातीय मामलों के केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश में 2014 से पहले देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे, अब देश में 696 मेडिकल कॉलेज हैं।

मंत्री ने कहा कि उन्होंने कहा कि देश में 2014 से पहले देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे, अब देश में 696 मेडिकल कॉलेज हैं। उन्होंने कहा कि 2014 तक देश में सिर्फ सात एम्स थे, जो 2022 में बढ़कर 22 हो गये। झारखंड के देवघर में भी एम्स शुरू हो गया है। केन्द्रीय मंत्री शुक्रवार को मांडर विधानसभा क्षेत्र में जाने के क्रम में भाजपा गोविन्दपुर मंडल द्वारा आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभारी होना चाहिए। मंत्री ने कहा कि कोविड काल में जिस तेजी से कोरोना फैल रहा था, उसी तेजी के



साथ बीमारी से लड़ने की दवा का अनुसंधान किया गया और आज वैक्सीन के कारण हम अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन गोविन्दपुर मंडल अध्यक्ष रामध्यान सिंह और धन्यवाद ज्ञापन लखन साहू ने किया।

इस मौके पर जिलाध्यक्ष चन्द्र शेखर गुप्ता, जिला सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार, जिला उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद सोनी, घुरन महतो, युवा मोर्चा अध्यक्ष विनय गुप्ता, सतोष जयसवाल, श्याम प्रसाद सोनी, जगरनाथ साहू सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सेना में संविदा पर नियुक्ति लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ : झामुमो

नवप्रदेश संवाददाता

रांची : झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने अग्निपथ योजना के विरोध में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार की नयी अग्निपथ योजना के विरोध में झामुमो भी उतर आया है। भट्टाचार्य शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कांफ्रिंस में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि पार्टी का मानना है कि सेना में संविदा पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर केंद्र सरकार ने देश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा है कि आज केवल छह माह की ट्रेनिंग देकर देश के युवाओं को फौज में भेजने की तैयारी हो रही है। एनसीसी की जुनियर ट्रेनिंग भी दो साल और सीनियर ट्रेनिंग तीन साल की होती है, तो क्या अग्निपथ योजना से देश के युवा एनसीसी से भी ज्यादा दक्ष हो जाएँगे।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसे मूर्ख बना रही है। पिछले दो वर्षों से सेना में नौकरी नहीं दी जा सकी है। कई राज्यों में पिछले चार से छह वर्षों में पुलिस फोर्स की नौकरी नहीं दी गयी। तीन साल से देश में किसी भी पैरामिलिट्री में नौकरी नहीं मिली। बच्चे तीन-चार साल से रोजगार के लिए मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद इनके

रातू में 40,000 रुपए में एक हाईवा बिक रहा बालू

नवप्रदेश संवाददाता

रातू : एक तरफ जनता बालु के लिए परेशान है दुसरी तरफ सरकार को जनता की जरूरत से कोई मतलब ही नहीं। सरकार द्वारा बालु पर प्रतिबंध से बालु काराबारियों के पौ बारह है।बालु कारोबारी बालु में प्रतिबंध का बात करते हुए कहते है कि बालु महंगा हो गया है। नदी से लाने में काफी खर्च करना

पड रहा है।जिसके कारण बालु महंगा है।अब सच्चाई क्या है यह समझ से बाहर है। एक बालु कारोबारी ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि पांच थानो में तीन-तीन हजार देना पडता है अब आप ही बताएं बालु कितना में मिलेगा।रातू ठाकुरगांव सडक पर रात होते ही बालु का आना जाना शुरू हो जाता है। बालु कारोबारी कहते है बालु जितना चाहिए उतना मिलेगा लेकिन पैसा एक हाईवा पर 40,000 लेगेगा। बालु कारोबारियो

के बालु जहां डंप होते है वहां भरपुर बालु है।वहां से ट्रैक्टर में बालु जरूरतमंद को भिजवाया जा रहा है।पहले अगर बालु कारोबारी को एक हाईवा में दो से पांच हजार की बचत होती थी लेकिन अब बालु कारोबारी को एक हाईवा में 10 हजार से ज्यादा की बचत हो रही है। तो फिर बालु में छुट मिले या ना मिले क्या अंतर पडता है लेकिन यह सच है कि बालु खुब बिक रहे है।

के नाम से खदान लेने में मशगूल हैं। अगर यही स्थिति और यही सरकार रही कुछ दिनों में पूरा राज्य बिक जायेगा। इसलिए अभी मौका है इस चुनाव में जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करें और इस निकम्मी सरकार को सबक सिखाने का काम करें। मौके पर हटिया विधायक नवीन जायसवाल, भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर, मनोज बाजपेयी, हेमलता उरांव, नरेंद्र सिंह, संजीव तिवारी, राजनाथ सिंह, मुकेश प्रसाद सहित अन्य मौजूद थे।

कांग्रेस परिवार व पैसे के लिए करती है राजनीति : बाबूलाल

नवप्रदेश संवाददाता

मांडर : पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को सोसई आश्रम में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने मांडर उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवार व पैसे के लिये काम करती है जिसका उदाहरण वर्तमान चुनाव भी है। जिसमें कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक के परिवार के सदस्य को ही उम्मीदवार बनाया है। इस चुनाव में



भाजपा को वोट देकर इन्हें चोट देने की जरूरत है। बाबूलाल ने कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार में हर तरफ

भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यहां जनता का कोई भी काम बगैर पैसे के नहीं होता है। अपना घर बनाने के लिये अपने गांव के नदी

नाला से बालू लाने पर लोगों को पुलिस पकड़ कर जेल में बंद कर दे रही है और मुख्यमंत्री इसे देखने के बजाय अपने व परिवार

एक नजर

मांडर विधानसभा क्षेत्र में कोवे मुंडा ने किया जनसंपर्क

खूंटी : तोरपा के विधायक कोचे मुंडा ने शुक्रवार को भी मांडर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर के समर्थन में लापुंग प्रखंड के कई गांवों में प्रचार अभियान चलाया। जन संपर्क के दौरान उनकी नजर शेड के नीचे हड़िया बेच रही महिलाओं पर पड़ी। विधायक वहां पहुंचे और उनसे बातचीत की। उन्होंने महिलाओं की इस स्थिति के लिए राज्य की हेमंत सरकार को जिम्मेवार बताया। विधायक मुंडा ने कहा कि राज्य की यूपीए सरकार ने हम सभी से झूठे वादे कर वोट लिया कि हमारी सरकार बनेगी, तो आप जैसी तमाम महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा, आपको हड़िया बेचने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अब तक सरकार ने कुछ नहीं किया और गरीब और लाचार महिलाएं हड़िया बेचकर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। हड़िया बेच रही महिलाओं ने विधायक को बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण हड़िया बेचकर परिवार चला रही हैं। विधायक ने कहा कि मांडर विधानसभा क्षेत्र में आप सबों को फिर एक बार अवसर मिला है अपनी भूल सुधारने का। इस लिए आप सभी भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर को वोट दें और आने वाले समय में पुनः भाजपा की सरकार बनायें।

पशुपालन और मधुमक्खी पालन का दिया प्रशिक्षण

खूंटी : समेकित आजीविका फार्म करां की किसान पाठशाला में तोरपा प्रखंड की आजीविका कृषक मित्र दीदीयों और कर्मियों का शुक्रवार को एक्सपोजर विजिट कराया गया। समेकित आजीविका फार्म, करां में कृषक मित्र दीदीयों को गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन और मधुमक्खी पालन के बारे प्रशिक्षण दिया गया तथा फार्म का परिभ्रमण कराया गया। जेएसएलपीएस के संजय पाण्डेय ने कृषक मित्रों को सूक्ष्म टपक इकाई और केचुवा उत्पादन के विषय में जानकारी दी। खूंटी जिला के जेएसएलपीएस डीपीएम सैलेश रंजन व आत्मा खूंटी से आये अमरेश ने कृषक मित्रों को उन्नत खेती के बारे में बताया। समेकित आजीविका फार्म करां में एक साथ इतने गतिविधि को देखकर कृषक मित्र काफी प्रभावित हुए और दोबारा आने की इच्छा जाहिर की।

कुएं में डूबने से महिला की मौत

खूंटी : तोरपा थाना क्षेत्र के ईचा आंगाटोली गांव के एक कुएं में डूबने से रंदय आईद (38) की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रंदय शुक्रवार को पानी भरने के लिए कुएं में गई थी। उसी दौरान पैर फिसलने से वह कुएं में जा गिरी। तैरना नहीं आने के कारण वह पानी में डूब गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों को सौंप दिया।

एसवीईईपी कार्निवल प्रोग्राम का आयोजन आज

बेड़ो : मांडर विधानसभा उपचुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रखंड प्रशासन द्वारा बीडीओ डॉ प्रवीण कुमार के नेतृत्व में शनिवार को एसवीईईपी कार्निवल प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। जिसके तहत फुटबॉल मैच, गीत नृत्य,रंगोली प्रतियोगिता चित्रांकन प्रतियोगिता एवं मतदान से संबंधित अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री छवि रंजन कुमार उपायुक्त रांची होंगे। वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को जागृत करने और अधिक से अधिक मतदाताओं द्वारा आगामी विधानसभा उपचुनाव में मतदान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

दो अलग-अलग सड़क हादसा में तीन घायल, दो रिस्स रेफर

बेड़ो : बेड़ो थाना क्षेत्र के कॉलेज गेट के समीप रांची गुमला मुख्य मार्ग पर शुक्रवार की अपराह्न लगभग डेढ़ बजे केशा बेड़ो निवासी 17 वर्षीय मो शमीम पिता मो अलीम सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसे ग्रामीण ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां डा प्रियंका ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए शमीम को रिस्स रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार शमीम एस एस प्लस टू उच्च विद्यालय बेड़ो में कक्षा नौवी की परीक्षा देने के लिए अपने घर से बेड़ो आ रहा था। जो अज्ञात वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर दूसरी घटना शाम साढ़े चार बजे की है जिसमें थाना क्षेत्र के पुरना पानी लापुंग सड़क पर जोगीमारा गांव के समीप बाइक सवार 18 वर्षीय जीतराम उरांव पिता बुधु उरांव व 15 वर्षीय अजय उरांव पिता जीतराम उरांव दोनों पंडा मसिया भरनो थाना गांव निवासी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेड़ो पहुंचाया जहां डा प्रियंका ने घायल दोनों युवकों का प्राथमिक उपचार कर गंभीर रूप से घायल जीतराम उरांव को बेहतर उपचार के लिए रिम्स रेफर कर दिया।

प्रधानमंत्री के विकास कार्यों पर जनता को भरोसा : अन्नपूर्णा

रांची : केन्द्रीय शिक्षा राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज मांडर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में सघन जनसंपर्क अभियान चलाते हुए भाजपा उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर को जिताने की अपील की। अन्नपूर्णा देवी ने पूर्वी सेमरा,चचगुरा गुडगांव, चिनारों,पुरियो, जरिया,हरिहरपुर,मेहगांव में जनता के बीच पहुंचकर जनता से संवाद करते हुए हेमंत सरकार की विफलता एवम मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार विकास विरोधी सरकार है। इसे उपचुनाव में सबक सिखाने का एक अवसर आया है। कहा कि यह सरकार आदिवासी विरोधी,दलित विरोधी,महिला विरोधी ,पिछड़ा विरोधी सरकार साबित हुई है। पंचायत चुनाव में इस सरकार ने जनता को पूरी तरह धोखा दिया जिसके कारण जनता ने भी इसे अपनी ताकत का अहसास करा दिया है। आज सभी जिलों में गांव की सरकार भी भाजपा की सरकार बन रही। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने बढ़ते बलात्कार,उत्पीड़न ,कल्याणकारी योजनाओं का बंद होना से ऊबकर हेमंत सरकार के खिलाफ वोट किया। उसी के तर्ज पर इस उपचुनाव में भी जनता सत्तापक्ष के खिलाफ मतदान करके भाजपा प्रत्याशी को जिताएंगी।

फार्मेट सी-1 : आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा					
वर्ष 2011 के इन्ट्रयूजे (सिविल) सॅ. 536 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 5 सितम्बर 2018 के निर्णय के अनुसार (जनहित फाउंडेशन एवं अन्य बनाम सच और एनआर)					
अन्वर्थी का नाम एवं पता	: सुभाष मुंडा, ग्राम : दलादिली, पो-सगरोम, थाना-नागड़ी, जिला-रांची, झारखंड				
राजनैतिक दल का नाम	: कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट), विषयकमॉ लेन, रांची- 834001				
चुनाव का नाम	: 66 मांडर (अ.ज.जा.) विधानसभा उपचुनाव 2022				
निर्वाचन क्षेत्र का नाम	: 66 मांडर (अ.ज.जा.) विधानसभा उपचुनाव 2022				
क्रम संख्या	लखित आपराधिक मामले	दोषसिद्ध आपराधिक मामलों के बारे में विवरण			
न्यायालय का नाम	मामले की संख्या तथा स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा और अपराध का संक्षिप्त विवरण	न्यायालयों के नाम एवं आदेश की तिथि	दोषसिद्ध तथा सजा के मामले का विवरण	
1.	सीजेएम कोर्ट, रांची	जीआर 2790 /2013 साक्ष के लिए लखित	धारा 143, 341, 342 आईपीसी रांची सभाग्रहायल के गेट पर धरना एवं जाम करना	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	न्यायिक दंडाधिकारी रांची	चान्हों थाना केस नं. 145 /21 मामला लखित	धारा 147, 148, 149, 341, 353, 188, 269, 270 आईपीसी नाजायज मजना लगाकर लाकड़ान का उलंघन, सरकारी काम में बाधा	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रांची	मांडर थाना केस नं 167/ 21 मामला लखित	धारा 147, 148, 149, 447, 341, 323 आईपीसी मारपीट करना	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	न्यायिक दंडाधिकारी रांची	चान्हों थाना केस नं. 193/ 2021 मामला लखित	धारा 147, 148, 149, 341, 323, 337, 338, 353, 427 आईपीसी नाजायज मजना लगाकर हत्ये हथियार से लैस होकर मारपीट कर जख्मी करना व सरकारी काम में बाधा	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	न्यायिक दंडाधिकारी रांची	चान्हों थाना केस नं. 194 /21 मामला लखित	धारा 147, 148, 149, 341, 323, 504, 506 आईपीसी नाजायज मजना वाककर हत्ये हथियार से लैस होकर मारपीट करना	लागू नहीं	लागू नहीं

एक साथ कई चुनौतियां

वर्तमान में देश में एक साथ कई चुनौतियां खड़ी हो गयी हैं। महंगाई और बेरोजगारी के मोर्चे पर तो सरकार लड़ ही रही है। विपक्ष भी इन मुद्दों पर हमलावर बना हुआ है। उसके बाद नुपूर शर्मा के बयान पर देश में बवाल मचा हुआ है। इसके कारण अब लगातार दूसरे शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के वक्त कई राज्य सरकारों को सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव करनी पड़ी। देश के कई शहरों में दिनभर तनाव का माहौल रहा। फिर इसी क्रम में भारत सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में तीन दिनों से बवाल मचा हुआ है। आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें जला दी गयी हैं। 7-8 राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में 11 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं। उसके पहले इस तरह के हालात चिंताजनक हैं, क्योंकि कई लोग इसी बहाने राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश करेंगे। केन्द्र एवं राज्य सरकारों को इन हालातों पर नियंत्रण पाने की तेज पहल करनी चाहिए।वर्तमान में सर्वाधिक नुकसान देश को अग्निपथ योजना के कारण हो रहा है। भले ही सशत्रु बलों की भर्ती नीति और सम्पूर्ण रक्षानीति में एक युग परिवर्तनकारी सुधार क्यों न हो, लेकिन अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं में जो तुषारन खड़ा हो रहा है, उसे देखते हुए अग्निपथ भी कृषि कानूनों की राह चलता हुआ नजर आ रहा है। कृषि कानूनों के मामले में तो सरकार काफी समय तक आक्रामक मुद्रा में रहने के बाद रक्षात्मक मुद्रा में आयी थी, लेकिन इस ओर योजना की घोषणा करते ही सरकार और सत्ताधारी दल को अपने फैसले के पक्ष में अपनी पूरी राजनीतिक ताकत झोंकनी पड़ रही है। भाजपा के सभी प्रवक्ता, केन्द्र सरकार के मंत्री और भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री अग्निपथ के समर्थन में आ गये हैं। सभी मुख्यमंत्री अग्निवीरों की सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता का आश्वासन दे रहे हैं। इसके बाद भी आंदोलन थम नहीं रहा है। फौज के सेवानिवृत्त अफसरों का बहुमत भी इस योजना के पक्ष में नहीं है। बेरोजगारों के अभिभावक भी अपने बच्चों को चार साल की नौकरी से खुश नहीं हैं। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों से भारत की सीमाओं को महफूज बनाये रखने के लिए थल सेना में प्रतिवर्ष करीब 60,000 सैनिकों की बहाली होती है। कोरोना महामारी के कारण पिछले दो साल भर्तियां बंद रहीं। अब महामारी से लगभग मुक्ति मिली तो नौजवानों को उम्मीद बंधी थी कि सेना में कम से कम एक लाख अवसर तो खुल ही जायेंगे। लगभग 1.12 लाख रिक्तयां भी बतायी जा रही हैं। भर्ती की घोषणा की भी गयी, परंतु चार वर्षों की अस्थायी नौकरी की बात सुनते ही अभ्यर्थियों ने बवाल खड़ा कर रखा है। बेरोजगार छात्र उबल पड़े हैं। यह आंदोलन उन्हीं राज्यों में ज्यादा हो रहा है, जहां के नौजवान सेना में ज्यादा संख्या में भर्ती होते हैं तथा उसकी तैयारी करते रहते हैं। इसलिए इस मामले में केन्द्र सरकार को त्वरित कदम उठाने की जरूरत है।

सामयिकी

जी हुजूर! सरकार की मुसीबत

डा. वेदप्रताप वैदिक

मोदी सरकार ने जो नई अग्निपथ योजना घोषित की है, उसके खिलाफ सारे देश में जन-आंदोलन शुरू हो गया है। यह आंदोलन रोजगार के अभिलाषी नौजवानों का है। यह किसानों और मुसलमानों के आंदोलन से अलग है। वे आंदोलन देश की जनता के कुछ वर्गों तक ही सीमित थे। यह जाति, धर्म, भाषा और व्यवसाय से ऊपर उठकर है। इसमें सभी जातियों, धर्मों, भाषाओं, क्षेत्रों और व्यवसायों के नौजवान सम्मिलित हैं। इसके कोई सुनिश्चित नेता भी नहीं हैं, जिन्हें समझा-बुझाकर चुप करवाया जा सके। यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त है। जाहिर है कि इस स्वतः स्फूर्त आंदोलन के भड़कने का मूल कारण यह है कि नौजवानों को इसके बारे में गलतफहमी हो गई है। वे समझ रहे हैं कि 75 प्रतिशत भर्तीयुवा जवानों को यदि चार साल बाद हटा दिया गया तो कहीं नहीं रहेंगे। न तो नई नौकरी उन्हें आसानी से मिलेगी और न ही उन्हें पेंशन आदि मिलने वाली है। इस आशंका का जिक्र मैंने परसों अपने लेख में किया था। इसे लेकर ही सारे देश में आंदोलन भड़क उठा है। रेलें चर गई हैं। सड़के बंद हो गई हैं और आंगनजी भी हो रही है। बहुत से नौजवान घायल और गिरफ्तार भी हो गए हैं। एक जवान ने आत्महत्या भी कर ली है। यह आंदोलन पिछले सभी आंदोलनों से ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर आंदोलनकारी वे ही नौजवान हैं, जिनके रिश्तेदार, मित्र या पड़ोसी पहले से भारतीय फौज में हैं। इस आंदोलन से वे फौजी भी अछूते नहीं रह सकते। सरकार ने इस अग्निपथ योजना को थोड़ा ठंडा करने के लिए भर्ती की उम्र को साढ़े 17 साल से 21 साल तक जो रखी थी, उसे अब 23 तक बढ़ा दिया है। यह राहत जरूर है लेकिन इसका एक दुष्परिणाम यह भी है कि चार साल बाद यानी 27 साल की उम्र में बेरोजगार होना पहले से भी ज्यादा हानिकर सिद्ध हो सकता है। यह ठीक है कि सेना से चार साल बाद हटने वाले 75 प्रतिशत नौजवानों को सरकार लगभग 12-12 लाख रुपये देगी तथा सरकारी नौकरियों में उन्हें प्राथमिकता भी मिलेगी लेकिन असली सवाल यह है कि मोदी सरकार ने इस मामले में भी क्या वही गलती नहीं कर दी, जो वह पिछले आठ साल में एक के बाद एक करती जा रही है? 2014 में सरकार बनते ही उसने भूमि-ग्रहण अध्यादेश जारी किया, अचानक नोटबंदी घोषित कर दी, कृषि कानून बना दिए और पड़ोसी देशों के मामलों में कई बार गन्धवा खा गई। इससे यही साबित होता है कि वह नौकरशाहों के मानदर्शन पर एक-अनेक देशहितकारी कदम उठाने का सत्ताहस तो करती है लेकिन उनके कदमों का जिन पर असली असर होता है, उन्हें वह बिल्कुल भी घास नहीं डालती है। वह बह भूल रही है कि वह लोकतंत्र की सरकार है। वह किसी बादशाह की सल्तनत नहीं है कि उसने जो भी हांक लगायी तो सारे दरबारियों ने कह दिया जी, हुजूर...!

(लेखक, भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष हैं।)



डा. दिलीप अग्निहोत्री

रक्षा

मंत्रालय की यह स्कीम युवाओं को देशसेवा का मौका देने के साथ ही उन्हें तकनीकी तौर पर भी सुधारने में मदद करेगी। इस योजना से विभिन्न क्षेत्रों में नए कौशल के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 'अग्निपथ' योजना के तहत सशस्त्र बलों का युवा प्रोफाइल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। अन्य देशों के मॉडल का अध्ययन किया गया। इसके बाद युवाओं के हित में निर्णय लिए गए हैं।

अभिव्यक्ति

अग्निपथ पर आंदोलनजीवियों का कहर

सरकार की गलत नीतियों का शांतिपूर्ण विरोध करना विपक्ष का अधिकार है। मगर विगत आठ वर्ष में सरकार का नकारात्मक विरोध ही होता रहा है।इससे अंततः विपक्ष की ही प्रतिष्ठा धुलित होती है। ऐसा लगता है कि विपक्षी पार्टियों की अपनी कोई नीति ही नहीं है। उसके नेता आंदोलनजीवियों का ही मनोबल बढ़ाते हैं। फिर उनकी लगाई आग में सियासी रोटी सेंकने का प्रयास करते हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में भी ऐसा ही आंदोलन शुरू हुआ है। इसका विरोध वहीं लोग कर रहे हैं, जिनमें आत्मानुशासन और आत्मविश्वास का अभाव है। चार वर्ष की सेवा के बाद भी रोजगार के अवसर समाप्त नहीं होंगे।अथर्था अर्थिक रूप से भी स्वावलंबी होंगे। सेना में चार वर्ष की सेवा जीवनशैली को बदल देगी। समाज और देश को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। इसके बाद वह जहां भी कार्य करेंगे, वह औरों से अलग दिखाई देगा। तब वह किसी आंदोलनजीवियों के इशारे पर राष्ट्रीय संपत्ति को आगे के हवाले नहीं करेंगे। फिलहाल वर्तमान सरकार के प्रत्येक कदम पर उपद्रव और हंगामा करने वाले एक बार फिर सक्रिय हैं। विगत आठ वर्षों के दौरान विकास के अनर्गलत कीर्तमान स्थापित हुए। सैकड़ों लोक कल्याणकारी योजनाओं से जन सामान्य को लाभान्वित किया गया। रक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत अभियान संचालित है। इसके उल्लेखनीय प्रमाण मिल रहे हैं। दशकों से लंबित लाखों करोड़ रुपये की परियोजनाओं को इस अवधि में पूरा किया गया।वन रैंक वन पेंशन की मांग चार दशकों से लंबित थी। वर्तमान सरकार ने इसे लागू किया । यूपीए सरकार के समय से सैन्य कमांडर राफेल लड़ाकू विमान सहित अनेक अस्त्र शस्त्रों को भारतीय सेना के लिए अपरिहार्य बता रहे थे। क्योंकि चीन अपनी सामरिक शक्ति लगातार बढ़ा रहा था। इस ओर भी वर्तमान सरकार ने ध्यान दिया।लंबित रक्षा सौदों का क्रियान्वयन हुआ। इसके साथ ही स्वदेशी रक्षा उत्पाद का नया अध्याय शुरू हुआ। आज भारत पचहत्तर देशों को रक्षा सामग्री का निर्यात कर रहा है। सीमा क्षेत्र में अभूतपूर्व निर्माण कार्य किए गए। कोई भी सरकार देश के सभी युवाओं को सरकारी नौकरियां नहीं दे सकती। इसको ध्यान में रखते हुऐ स्वरोजगार की अनेक योजनाएं लागू की गईं।



अग्निवीरों में से पच्चीस प्रतिशत को सेना की सुव्यवस्थित सेवा में समायोजित करने की बात महत्वपूर्ण है। शेष युवाओं को अर्धसैनिक बल,असम राइफल्स आदि में प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाएगा।स्वरोजगार के लिए सरकार उनको प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराएगी। आंदोलनजीवियों को बताना चाहिए कि 17 से 21 आयु वर्ग के युवा कौन सी नौकरी कर सकते है। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय युवाओं को अग्निवीर भर्तियां 'अग्निपथ' योजना के दौरान ही शामिल होने का मौका दिया जाएगा। सेनाओं की ट्रेनिंग देने के बाद इन्हें पाकिस्तान-चीन सीमा पर तैनात किया जाएगा। सशस्त्र सेनाओं से निकलने के बाद इन 'अग्निवीरों' को केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों की नौकरियों में प्राथमिकता दी जायेगी। रक्षा मंत्रालय की यह स्कीम युवाओं को देशसेवा का मौका देने के साथ ही उन्हें तकनीकी तौर पर भी सुधारने में मदद करेगी। इस योजना से विभिन्न क्षेत्रों में नए कौशल के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 'अग्निपथ' योजना के तहत सशस्त्र बलों का युवा प्रोफाइल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। अन्य देशों के मॉडल का अध्ययन किया गया। इसके बाद युवाओं के हित में निर्णय लिए गए हैं। अग्निवीर भविष्य के लिए तैयार इस सैनिक का हिस्सा होगा। अग्निवीर भारत के युवा रक्षक होंगे। चार साल सेना में रहने के बाद अग्निवीर का बायोडाटा बहुत ही अנוखा होगा। वह देश के अन्य युवाओं की भीड़ से अलग होगा। देश के साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को सशस्त्र बलों की सेवा करने का मौका दिया जायेगा। इन्हें 4.76 लाख से 6.92

लाख रुपये का सालाना पैकेज दिया जाएगा। अग्निवीरों को उच्च तकनीकी वातावरण में प्रशिक्षित किया जाएगा। अगले एक दशक में सेना का आधा हिस्सा अग्निवीर होंगे। इस साल चालीस हजार भर्तियों से शुरूआत की जाएगी। सशस्त्र बलों में अधिकारियों को छोड़कर सभी भर्तियां 'अग्निपथ' योजना के तहत ही की जाएंगी। चार वर्षों के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती करने की योजना से सेना की व्यावसायिकता, रेजिमेंटल लोकाचार और लड़ाई की भावना प्रभावित होंगी। कार्यक्रम का उद्देश्य रक्षा कर्मियों को नागरिक क्षेत्र में नौकरियों के लिए तैयार करना है। अग्निवीरों की भविष्य की करियर संभावनाओं को बढ़ाने के लिए और उन्हीं नागरिक क्षेत्र में विभिन्न नौकरी की भूमिकाओं के लिए सुसज्जित करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय रक्षा कर्मियों की सेवा के लिए एक विशेष, तीन वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू कर रहा है जो रक्षा प्रतिष्ठानों में उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा प्राप्त कौशल प्रशिक्षण को मान्यता देगा। इस कार्यक्रम को इन्गू द्वारा डिजाइन और निष्पादित किया जाएगा। अग्निवीरों को स्नातक डिग्री के लिए आवश्यक पचास प्रतिशत क्रेडिट कौशल प्रशिक्षण तकनीकी और गैर-तकनीकी से आएगा और शेष पचास प्रतिशत भाषा, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, गणित, शिक्षा, वाणिज्य, पर्यटन, व्यावसायिक अध्ययन, कृषि और ज्योतिष, पर्यावरण अध्ययन और संचार कौशल में एंबिलिटि इन्हासमेंट कोर्स जैसे विषयों की एक विस्तृत विविधता को कवर करने वाले पाठ्यक्रमों से आएगा। यह कार्यक्रम यूजीसी

मानदंडों के साथ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अनिवार्य राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें कई निकास बिंदुओं का भी प्रावधान है। तीन वर्ष की समय सीमा में सभी पाठ्यक्रमों के पूरा होने पर डिग्री मिलेगी। इस कोर्स को रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में न केवल भारत में बल्कि विदेश में मान्यता प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केन्द्र सरकार की ह्यअग्निपथ योजनाह भारतीय युवाओं के लिए एसस्त्र बलों में सेवा के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना है। अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा के उपरान्त प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा एवं सम्बन्धित अन्य सेवाओं की नौकरियों में प्राथमिकता प्रदान करेगी। अग्निपथ योजना के माध्यम से युवाओं को देश की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का अनूठा अवसर प्राप्त होगा। यह योजना देश की तीनों सेनाओं की मानव संसाधन नीति में एक नए युग की शुरुआत है। इससे सशस्त्र बलों का प्रोफाइल युवा और ऊर्जावान होगा। सशस्त्र बलों में युवा और अनुभवी कर्मियों के बीच एक अच्छा संतुलन सुनिश्चित होगा। अग्निपथ योजना के तहत दसवीं पास 'अग्निवीर' नौकरी के दौरान राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से बारहवीं कक्षा का प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे। प्रमाणपत्र पूरे देश में नौकरी और उच्च शिक्षा के लिए मान्य होगा। इससे अग्निवीरों को जीवन में बाद में समाज में उच्चापक भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त शैक्षिक योग्यता और कौशल हासिल करने में मदद मिलेगी।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

खफा अरब, क्यों भारत के लिए खास आसियान



आरके सिन्हा

शांति एवं मित्रता, धर्म व संस्कृति, कला एवं वाणिज्य, भाषा और साहित्य के क्षेत्रों में अत्यंत प्रगाढ़ हो चुके थे चिरस्थायी रिश्ते अब भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया की शानदार विविधता के हर पहलू में मौजूद हैं। भारत ने 1991 के बाद व्यापक बदलावों के साथ दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। तब ही से भारत की विदेश नीति में आसियान बेहद खास हो गया।

राजधानी के दिल लुटियन दिल्ली के तुगलक क्रिसेंट में बना सुंदर भारत-आसियान मैत्री पार्क गवाही है कि भारत आसियान देशों से अपने संबंधों को खास अहमियत देता है। इसका उदाहरण तत्कालीन विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज ने सन 2018 में किया था। राजधानी में बीते दिनों आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की भारत ने मेजबानी की। इसमें भारत-आसियान देशों के आपसी संबंधों पर चर्चा हुई। महत्वपूर्ण ये भी है कि ये सम्मेलन तब हुआ जब दुनिया के कई इस्लामिक देशों ने नुपूर शर्मा की हजरत मोहम्मद पर की गई ओछी टिप्पणी पर अपना विरोध जताया था। इन्में इंडोनेशिया और मलेशिया भी हैं। ये आसियान के सदस्य होने के साथ-साथ इस्लामिक देश भी हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें किआसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसका मकसद आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना है। इसके सदस्य देश हैं- ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, तिमोर-लेस्ते, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।

चालू साल 2022 को भारत-आसियान मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत की एक्ट ईस्ट नीति और व्यापक हिंद-प्रशांत विजन के लिए भारत के विजन में आसियान की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करते रहे हैं। कोविड-19 का असर जब अपने चरम पर था तब भारत ने म्यांमार के लिए आसियान की मानवीय पहल के लिए दो लाख अमेरिकी डॉलर और आसियान के कोविड-19 रिसॉर्स फंड के लिए दस लाख अमेरिकी डॉलर मूल्य की चिकित्सा सामग्री का योगदान दिया था। इसके चलते आसियान भारत के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है। भारत और आसियान के बीच व्यापक एवं बहुआयामी संबंध हैं और आगामी भारत-आसियान सम्मेलन में उच्चतम स्तर पर भारत-आसियान सामरिक साझेदारी के भविष्य को नई दिशा देने का अवसर प्रदान करेगा। भारत-आसियान साझेदारी भले ही कोई बहुत पुरानी न हो हो, लेकिन दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के रिस्ते दो सहस्राब्दियों से भी अधिक पुराने हैं। शांति एवं मित्रता, धर्म व संस्कृति, कला एवं वाणिज्य, भाषा और साहित्य के क्षेत्रों में अत्यंत प्रगाढ़ हो चुके थे चिरस्थायी रिस्ते अब भारत और

दक्षिण-पूर्व एशिया की शानदार विविधता के हर पहलू में मौजूद हैं। भारत ने 1991 के बाद व्यापक बदलावों के साथ दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। तब ही से भारत की विदेश नीति में आसियान बेहद खास हो गया। भारत की आसियान को लेकर लुक ईस्ट नीति एवं एक्ट ईस्ट नीति ऊंची कारोबारी खलांग लगाने में अत्यंत मददगार साबित होती रही हैं। आसियान और भारत अब रणनीतिक साझेदार बन गए हैं। आसियान के प्रत्येक सदस्य देश के साथ भारत की राजनयिक, आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी बढ़ रही है। भारत और आसियान अपने समुद्रों को सुरक्षित और निरापद रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। भारत-आसियान व्यापार और निवेश प्रवाह बढ़ता जा रहा है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और भारत आसियान का सातवां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। भारत द्वारा विश्व में किए जाने वाले निवेश का 20 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा आसियान के ही खाते में जाता है। सिंगापुर की अगुवाई में आसियान भारत का प्रमुख निवेश स्रोत है। इस क्षेत्र में भारत द्वारा किए गए पु्क व्यापार समझौते अपनी तरह के सबसे पुराने समझौते हैं और किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में सबसे महत्वाकांक्षी हैं। यही नहीं, इसके परिणामस्वरूप दक्षिण-पूर्व एशिया में पर्यटन के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में अब भारत भी शामिल हो गया है। इस क्षेत्र में रहने वाले 60 लाख से भी अधिक प्रवासी भारतीय, जो विविधता में निहित और गतिशीलता से ओत-प्रोत हैं, हमारे लोगों के बीच आपसी मानवीय जुड़ाव बढ़ाने की दृष्टि से अद्भुत हैं। भारत-आसियान को बुद्ध धर्म भी जोड़ता है। अगर बात म्यांमार की करें तो भारत और म्यांमार के बीच 1600 किलोमीटर से ज्यादा लंबी साझा जमीनी और समुद्री सीमा है। दोनों के बीच मित्रता की जड़ें धार्मिक और सांस्कृतिक परम्पराओं में निहित हैं और दोनों की साझा बौद्ध विरासत हमें उनसे ही घनिष्ठ रूप से बांधे हुए है जितना पुराना हमारा ऐतिहासिक अतीत है। गांधीजी ने कई बार म्यांमार का दौरा किया था। बालगंगाधर तिलक को तो कई साल के लिए रंगून्ग भेजकर देश निकाला दे दिया गया था। भारत की

आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान ने म्यांमार में बहुत से लोगों को उर्देलित कर दिया था। इस बीच आसियान में मलेशिया भारत के तीसरे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर कर सामने आया है और भारत में निवेश करने वाला आसियान देशों में से महत्वपूर्ण निवेशक है। हिंद महासागर में केवल 90 समुद्री काल की दूरी पर स्थित भारत और इंडोनेशिया दो सहस्राब्दियों से सभ्यता आधारित एक संबंध की निरंतरता को साझा करते हैं। चाहे ओडिशा में वार्षिक बालीजात्रा का उत्सव हो या रामायण और महाभारत की कहानियां जो कि पूरे इंडोनेशियाई भू-क्षेत्र में दिखती हैं। आज, रणनीतिक सहयोगियों के रूप में भारत-इंडोनेशिया सहयोग राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा एवं सुरक्षा, सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच संबंधों जैसे सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है। आसियान में इंडोनेशिया हमारा लगातार सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी बना हुआ है। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले 10 वर्षों में 2.5 गुना बढ़ा है। इसके साथ ही,भारत और कंबोडिया के बीच परंपरागत और मैत्रीपूर्ण संबंध सभ्यताओं पर आधारित हैं जो गहराई से जुड़े हुए हैं। अंकोर वाट मंदिर का भव्य ढांचा हमारे प्राचीन ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का एक शानदार गवाह और भव्य प्रतीक है। 1986-1993 के मुस्लिम समय में अंकोर वाट मंदिर का पुरस्कार और पुनर्स्थापन कार्य करने में भारत गौरवान्वित हुआ। और सिंगापुर की संक्षिप्त में चर्चा किए वगैर हम भारत-आसियान संबंधों के साथ न्याय नहीं कर सकते। सिंगापुर पूर्व के साथ हमारे प्रवेश का मुख्य मार्ग है। यह हमारा प्रमुख आर्थिक साझेदार है और महत्वपूर्ण सामरिक सहयोगी भी है जिसकी झलक कई क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों में परिलक्षित होती है। 16 भारतीय शहरों से सिंगापुर के लिए सप्ताह में 240 सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। सिंगापुर की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से भारतीय पर्यटक समूह तीसरे स्थान पर है। भारत- आसियान सम्मेलन में उन तमाम बिन्दुओं पर विचार रूप से चर्चा हुई, जिससे कि दोनों को दीर्घकालिक लाभ हो।

(लेखक, वरिष्ठ संपादक, संपर्कार और पूर्व सांसद हैं।)

मोदी सरकार का सपना-सशक्त भारत हो अपना



गिरिराज सिंह

आज देश आजादी के 75वें वर्ष के रूप में अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के वीर सपूतों के सपने को जाकर करने के लिए सरदार पटेल ने जो मजबूत नींव रखी थी उस पर पिछले आठ साल में मोदी सरकार ने बुलंद इमारत बनाई है। केन्द्र सरकार ने 2047 में भारत के भव्य स्वरूप की रूपरेखा तैयार ही नहीं की है बल्कि उस पर तेजी से अमल शुरू कर दिया है। आप देखें कि किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी घर को अगर आंका जाए तो आर्थिक स्वतंत्रता और इंफ्रॉस्ट्रक्चर आधार होता है। देश में किस चीज को मोदी की गली देनी है और वह विदेशों में जाकर देश को ही गाली देने लगते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया में मोदी ने भारत की साख बढ़ाई है। इसके कारण एफडीआई

36 बिलियन डॉलर से बढ़कर 85 बिलियन डॉलर हो गई है। विश्वीय मुद्रा भंडार 300 बिलियन डॉलर से बढ़कर 607 बिलियन डॉलर हो गया है। पूरी दुनिया में मोदी जी ने भारत की विश्वसनियता को बढ़ाया है। इसके कारण देश आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गया है। यही नहीं 2014 में जहां निर्यात 19 लाख करोड़ रुपये प्रतिवर्ष था। आज वह बढ़कर 33 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की स्थिति में भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की। इसके कारण कोरीनाकाल में कृषि आधारित उत्पादनों के निर्यात में 23 फीसदी वृद्धि हुई है। मैं अगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सपनों को गांव की ओर ले चलू तो उन्होंने ग्रामीण इंफ्रॉस्ट्रक्चर से लेकर शहरों के नेशनल हाइवे और सड़कों का भी एक जाल बिछाया है। दुनिया में जिस देश ने तस्करी की है, वह इंफ्रॉस्ट्रक्चर को मजबूत करके ही है। पिछले 7 सालों में नेशनल हाइवे का निर्माण 300 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। 2015 में जहां भारत में नेशनल हाइवे 1389 किमी सालाना बनता था, वहीं 2021-22 में हमारी सरकार ने 4,000 किलोमीटर की सड़कें प्रतिवर्ष बनाने का काम किया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि ग्रामीण भारत को देश की आर्थिक रीढ़ माना जाता है तो गांव को नेशनल हाइवे से जोड़ना पड़ेगा और जब तक नेशनल हाइवे गांवों तक नहीं बनेगा तब तक गांव की सड़क एक सीमित स्थल तक ही रुक जाएगी और गांव की चीजों को देश के एक छोर से दूसरी छोर ले जाने में आज जो सुविधा मिल रही है वह नहीं मिल पाती। इसलिए 2025 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र



मोदी का सपना है कि 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाइवे बनाना है और यह एक सशक्त भारत का सपना है। आजादी के बाद सरकारें तो आती और जाती रहीं, काग्रेस सरकार हगरीगी हटाओह्म का नारा देती रही परन्तु गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। पहली बार मूलभूत सुविधा देने का काम मोदी सरकार ने किया। काग्रेस ने इंदिरा आवास योजना बनाकर अपने ही नेताओं का महिमामंडन किया। परंतु गरीबों के बारे में वास्तव में नरेन्द्र मोदी जी ने सोचा और गरीबों को छत दी और वह भी पूरे सम्मान के साथ। गरीबों का सपना, जो रोटी, कपड़ा और मकान के लिए मजबूर थे, उन्हें मोदी सरकार ने पूरा किया। 2014 तक केवल 3.25 लाख करोड़ मकान ही बन पाए थे, लेकिन मोदी सरकार ने पिछले 8 साल में ढाई करोड़ से ज्यादा मकान बनाने का काम किया और उन्हें न केवल आवास दिया बल्कि उनके लिए शौचालय भी

दिया। शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए काग्रेस के पास कोई सोच नहीं थी। कोई योजना नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए शहरी आवास योजना बनाई और अभी कई मकान पाइपलाइन में हैं, जो गरीबों को सुपुर्द किए जाएंगे। गरीबों का जो सपना है, उसे पूरा करने के लिए हम दिन-प्रतिदिन प्रयत्नशील हैं। पहले इंदिरा आवास योजना में केवल मकान था, हमने घर में केवल शौचालय ही नहीं दिया, बल्कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से खाना बनाने के लिए गैस, उजाला के तहत उन घरों में रोशनी पहुंचाई और जन धन योजना के तहत 2 लाख रुपये के बीमा सहित बैंक के अकाउंट भी खुलवाए। आज देश में लगभग 45 करोड़ गरीबों के खाते खोले जा चुके हैं। पहले लोग मजाक उड़ाते थे कि इससे क्या मिलेगा, लेकिन जब भारत सहित विश्व कोरोना वायरस की चपेट में आया, रोजगार, जान-माल सभी खतरे में पड़ गए, उस समय उन खातों में पैसे मोदी सरकार ने भेजे। 80 करोड़ गरीब लोगों को गरीब कल्याण योजना के तहत राशन मुहैया करवाया गया। प्रधानमंत्री जी को चिंता थी कि किसी भी घर में कोई भी भूखा न सोए, कोई भूख के कारण ना मरे। मोदी जी ने गरीबों के घर में राशन पहुंचाया और वह आज फिर से नई जिंदगी की शुरूआत कर रहे हैं। गांवों में 2005 में बड़े जोर-शोर से काग्रेस के शासन में मनरेगा जैसी योजना लाई गई और उस मनरेगा जैसी योजना में गरीबों के पास उनकी मजदूरी कम जाती थी और वह भ्रष्टाचार एवं बिचौलियों की भेंट चढ़ जाती थी। काग्रेस और विपक्षियों ने सदन के

अंदर मोदी जी को घेरने का काम किया। उनको लगता था कि मोदी जी मनरेगा को बंद कर देंगे, परंतु प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं इसे बंद नहीं करूंगा, इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सशक्त आधार बनाऊंगा, यह जीविकोपार्जन का सशक्त आधार होगा। आप देखें कि 2014 में मनरेगा में केवल 33 हजार करोड़ रुपये का बजट था और आज लगातार पिछले कई वर्षों से एक लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट है और जरूरत पड़ने पर यह बजट 1 लाख 12 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचा। यही नहीं इसमें मजदूरों की भागीदारी, जिनको काम नहीं मिल रहा था, उन हाथों में रोजगार देने की भागीदारी भी बढ़ी। जैसे 2006-07 से 2013-14 के बीच केवल 1660 करोड़ कुल श्रम दिवस सृजित हुए थे और 2014-15 से आज तक देखें तो लगभग ढाई हजार करोड़ श्रम दिवस सृजित हुए हैं, लेकिन अगर वहीं बजट देखें तो 2006-07 से 2013-14 तक केवल 2,13,220 करोड़ रुपये था। आज मोदी सरकार ने 5,21,127 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, केवल खर्च ही नहीं हुए, पहले मनरेगा में बैंकों के द्वारा डीबीटी नहीं होती थी और बिचौलिये पैसे खा जाते थे। आज 99% बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में मजदूरों को आर्थिक संबल मिला है। उस पर पारदर्शी तरीके से टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है जिससे पारदर्शिता के साथ भुगतान भी हो और काम भी हो। आज मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 54% हो गई

है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने इंफ्रॉस्ट्रक्चर पर, नेशनल हाइवे पर, वाटरवेज पर एवं एयरवेज पर जोर दिया। जब उन्होंने कहा कि हवाई चपल पहनने वाला हवाई जहाज से यात्रा करेगा, तो विश्वभेे में मजाक उड़ाया। गांव की कहावत है जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। प्रधानमंत्री मोदी जी एक चाय बेचने वाले के बेटे थे और उन्होंने गरीबी देखी थी। आज उन्हीं गरीबों का सपना पूरा करने का प्रण प्रधानमंत्री जी ने लिया है। मैं बिहार से आता हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि दरभंगा में भी हवाई जहाज उतरेगा और वहां के गरीब मजदूर, किसान हवाई जहाज की यात्रा करेंगे एवं फौर लेन की सड़क से जाएंगे। आज उन सड़कों को हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जोड़ने का एवं गुणवत्तायुक्त बनाने का काम कर रहे हैं। सन 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने समृद्ध गांव, ग्राम स्वराज का सपना देखा था और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की थी, जो पहाड़ी क्षेत्र, समतल क्षेत्र, नक्सली हिंसा से प्रभावित क्षेत्र सभी को शामिल करते हुए 100 की आबादी से ज्यादा घर वाले जगहों तक सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। आज उन सड़कों को मोदी जी ने गुणवत्तायुक्त बनाकर चौड़ीकरण करवाया। जहां 2007-14 तक केवल 2 लाख 98 हजार किलोमीटर सड़कें बनीं, वहीं आज हम लगभग मजबूती के साथ साढ़े तीन लाख किलोमीटर की ओर बढ़ रहे हैं।

(लेखक, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री हैं।)

मोदी सरकार को देश की 130 करोड़ जनता मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों को देख रही है आने वाला 2024 में देश की जनता मोदी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला विनोद तिवारी ईश्वरी सिंह शमीम अहमद रायन श्याम नारायण सिंह मिथिलेश सिंह सत्येंद्र सिंह रुद्र शुक्ला इंदु भगत युंकेश सिंह शशांक सुमन देवांग शुक्ला हर्ष सहानी रवीम खान जितेंद्र कमलापुरी गणेश नसि अशोक पासवान सिद्धार्थ प्रसाद गुप्ता कुश कुमार रामानंद पांडे शैलेश कुमार मेहता शमिम अंसारी उमेश यादव गंगा देवी उमेश पासवान अखण्ड पांडे रामानंद पांडे रमजान अखन नयूम बीबी सौरभ पांडे अलोक सिंग अमित सिंह मन्नु अंसारी सिंदू रायन मोनू रायन अशीष राम उदय यादव इत्यादि लोग उपस्थित थे।

